रणजीत टाइम्स

इंदौर

बुधवार, 20 मई, 2026

वर्ष-2 |अंक-122 |कुल पृष्ठ:8-Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

प्रदेश के विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए 30,055 करोड़ रूपये की कैबिनेट स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई।

मंत्रि-परिषद ने राज्य के कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति -2026 को भी मंजूरी दी है। राज्य के विभिन्न वर्गों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। इसमें वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजना के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये के साथ ही विभिन्न आपदाओं में किसानों को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इसके साथ ही श्रमिक कल्याण की योजनाओं के लिए 1,779.07 करोड़ रुपये, सिवनी और देवास की समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 593 करोड़ 24 लाख रुपये, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालन के लिए 373 करोड़ 38 लाख रुपये, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये तथा महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित शौर्य दल और चाइल्ड हेल्पलाइन योजनाओं के लिए 156 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

स्थानान्तरण नीति वर्ष 2026 का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने "राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2026" का अनुमोदन किया है। स्वीकृति अनुसार इस वर्ष 01 जून 2026 से 15 जून 2026 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल किया जायेगा। नीति में लिपिकीय त्रुटि सुधार, स्पष्टीकरण अथवा अन्य संशोधन करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है। पद एवं संवर्ग संख्या के आधार पर अधिकतम स्थानांतरण की संख्या का निर्धारण स्थानांतरण नीति में स्पष्ट किया गया है।

किसानों के हक में बड़ा फैसला

मंत्रि-परिषद ने किसानों को फसल हानि या क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगामी 05 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) तक निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11 हजार 608.47 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार पात्र कृषकों को प्रति कृषक प्रत्येक मौसम में न्यूनतम दावा राशि 1,000 रूपये का भुगतान करने के लिए दावा राशि और राशि 1000 के अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक नियम/दिशा-निर्देश जारी करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अधिकृत किया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजन की पेंशन योजना के लिए 15 हजार 184.42 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) योजना अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 1 अप्रैल 2026 से आगामी 05 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 2,123 करोड़ 42 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी महिलाओं को पात्रतानुसार प्रतिमाह 600 रूपये पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

शोरूम और बेलमोंट पार्क के दफ्तर में लगी आग

इंदौर. इंदौर में बुधवार सुबह दो स्थानों पर आग लगने से लाखों रुपये कीमत का फर्नीचर, दस्तावेज और अन्य सामान जल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को फैलने से रोका। आग लगने की घटना रिंग रोड के समीप महिदपुरवाला शोरूम पर हुई। आग बिल्डिंग के सातवें माले पर लगी और पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस बीच कर्मचारियों ने भी आग पर काबू पाने के लिए बिल्डिंग में मौजूद अग्नि सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग से सातवीं मंजिल का कुछ हिस्सा ही जला है। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इसके अलावा लसुड़िया क्षेत्र के बेलमोंट पार्क के दफ्तर में आग लग गई। आग से दफ्तर का फर्नीचर, दस्तावेज और अन्य सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक दफ्तर का ज्यादातर हिस्सा आग की चपेट में आ चुका था।

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मध्यप्रदेश बंद

भोपाल. मध्यप्रदेश में बुधवार को दवा कारोबार पर बड़ा असर देखने को मिला। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में प्रदेशभर के करीब 41 हजार मेडिकल स्टोर्स बंद रखे गए।

राजधानी भोपाल में भी 3 हजार से ज्यादा दवा दुकानों ने बंद का समर्थन किया, जिससे शहर के प्रमुख मेडिकल बाजारों में दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि अस्पताल परिसरों के भीतर संचालित मेडिकल स्टोर्स खुले रहे, ताकि गंभीर मरीजों को परेशानी न हो। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर किया गया। दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन फार्मेसी व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि बिना पर्याप्त निगरानी के दवाइयों की बिक्री मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है।

राजधानी भोपाल में सुबह से ही दवा व्यापारी एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। थोक दवा बाजार में कारोबारियों ने नारेबाजी की और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी भी की गई। कारोबारियों का कहना है कि मेडिकल स्टोर्स पर प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की मौजूदगी में दवाइयां दी जाती हैं, जबकि ऑनलाइन बिक्री में इस प्रक्रिया की सही निगरानी नहीं हो पाती।

दिव्यांग महिला को ई-केवाईसी समस्या से नहीं मिल रहा था राशन, प्रशासन ने मौके पर किया निराकरण

झाबुआ. शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से ग्राम पंचायत उदयपुरिया में शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के दौरान महिला आवेदक श्रीमती काली भूरिया ने राशन नहीं मिलने की समस्या बताई। इस पर कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर जांच एवं निराकरण की कार्यवाही की गई।

जांच के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुरेश तोमर द्वारा परिवार की जानकारी का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि परिवार को प्रतिमाह नियमित रूप से 15 किलो राशन आवंटित हो रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि परिवार का एक सदस्य मानसिक रूप से दिव्यांग एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिसकी उंगलियां मशीन में स्पष्ट नहीं आने के कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही थी तथा राशन वितरण में समस्या आ रही थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने खाद्य विभाग को तकनीकी समस्या के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुरेश तोमर द्वारा मौके पर ही दिव्यांग महिला का आधार कार्ड मंगवाकर फेस ई-केवाईसी कराने का प्रयास किया गया, किंतु तकनीकी कारणों से प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी। इसके पश्चात वरिष्ठ अधिकारी श्री पाटिल को अवगत कराते हुए भोपाल स्थित तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया गया तथा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री भास्कर गाचले के मार्गदर्शन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुरेश तोमर द्वारा मौके पर ही महिला को दो माह का अतिरिक्त राशन दिलवाया गया। महिला को 5-5 किलो अतिरिक्त राशन प्रदान किया गया। अब संबंधित परिवार को प्रतिमाह 15 किलो के स्थान पर 20 किलो राशन प्राप्त होगा। परिवारजनों ने जिला प्रशासन की त्वरित कार्यवाही की सराहना की।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुरेश तोमर ने बताया कि इसी दौरान राशन कम मिलने की शिकायत पर उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण भी किया गया। जांच में पाया गया कि दुकान का संचालन विपणन सहकारी संस्था थांदला द्वारा किया जा रहा है तथा नियमित विक्रेता के उपार्जन कार्य में व्यस्त रहने के कारण सहायक विक्रेता द्वारा वितरण कार्य संपादित किया जा रहा था, ताकि वितरण व्यवस्था प्रभावित न हो।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुरेश तोमर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न की तौल एवं कांटे का सत्यापन किया गया। 5 किलो के बांट से तौल कर खाद्यान्न की मात्रा सही पाई गई। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लिया गया, जिसमें अधिकांश उपभोक्ताओं ने निर्धारित पात्रता अनुसार राशन प्राप्त होना बताया। जांच में यह भी पाया गया कि अब तक 75 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों को राशन वितरित किया जा चुका है तथा प्रतिमाह औसतन 92 से 95 प्रतिशत तक वितरण किया जाता है।

महा-लापरवाही: शिवपुरी की 'हनुमान गली' बनी नरक!

5 महीने से सड़कों पर बह रहा गटर, सो रहा प्रशासन

शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट

शिवपुरी। एक तरफ जहां स्वच्छता के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं शिवपुरी के मुख्य बाजार से जुड़ी 'हनुमान गली' आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है।

पिछले 5-6 महीनों से इस पूरे इलाके में गटर का गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर खुलेआम बह रहा है। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों का जीना मुहाल हो चुका है, लेकिन प्रशासन कुंभकरणी नींद में सोया हुआ है।

'चुल्लू भर' सफाई और फिर वही हाल!

स्थानीय निवासी रिंकल सिंगल और अन्य दुकानदारों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब भी वे शिकायत करते हैं, तो नगर पालिका के लोग आकर नाममात्र की सफाई (कुछ-कुछ) कर के चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ तीन दिन बाद स्थिति फिर जस की तस हो जाती है। समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है।

"महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग... सबके पैर इस गंदगी में सन रहे हैं। त्योहार हों या आम दिन, हमें इस नरक से गुजरना ही पड़ता है।" » — पीड़ित निवासी

आक्रोश: "CM हेल्पलाइन से लेकर पार्षद तक सब फेल!"

दुकानदारों का गुस्सा जायज है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर वे हर दर वाजा खटखटा चुके हैं: CM हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन को ई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय पार्षद से गुहार लगाई गई, तो उन्होंने सिर्फ खानापूर्ति के लिए आदमी भेज दिए। नगर पालिका और PHE विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, पर नतीजा सिर्फ़ 'शून्य' रहा।

मासूम बच्चे और श्रद्धालु भुगत रहे सजा

यह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। माधव चौक से निकलने वाले बड़े-बड़े जुलूसों के लिए यह डायवर्शन रूट है और मुख्य बाजार को जोड़ता है। स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे रोज इस बदबूदार पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। मंदिर जाने वाली महिलाएं और श्रद्धालु पवित्र मन से निकलते हैं, लेकिन सड़कों पर बहती गंदगी उनके पैरों को दूषित कर रही है। बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, गंदगी अब लोगों के घरों और दुकानों के भीतर तक प्रवेश कर रही है, जिससे व्यापार भी ठप होने की कगार पर है।

हमारा प्रशासन से सीधा सवाल:

क्या शिवपुरी का नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़ी महामारी का इंतजार कर रहे हैं? जनता टैक्स समय पर देती है, तो उन्हें यह 'नरक' क्यों परोसा जा रहा है? स्थानीय निवासियों ने मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस गटर की समस्या का स्थायी निराकरण नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब देखना यह होगा कि इस धमाकेदार खुलासे के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटती है या हनुमान गली के लोग यूं ही नरक भोगने को मजबूर रहेंगे!

उज्जैन में महाकाल मंदिर की पार्किंग वाली जमीन भाजपा विधायक की कंपनी को बेच दी गई - कांग्रेस नेता उमंग सिंघार

भोपाल/उज्जैन। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने कहा कि उज्जैन में महाकाल मंदिर की पार्किंग वाली जमीन भाजपा विधायक की कंपनी को बेच दी गई।

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक जमीन सौदे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया है। सिंघार ने दावा किया है कि पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी जमीन को एक ऐसी कंपनी को बेच दिया गया, जिसका संबंध भाजपा के एक विधायक से है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस जमीन को मूल रूप से सरकारी संपत्ति के तौर पर तय किया गया था, उसे पहले प्राइवेट बनाया गया और फिर यूटोपिया होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया। इस कंपनी के डायरेक्टरों में आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय भी शामिल हैं। सिंघार ने सवाल उठाया कि क्या महाकाल लोक प्रोजेक्ट, जिसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के तौर पर पेश किया गया था, अब सिर्फ एक ऐसा जरिया बनकर रह गया है, जिससे रियल एस्टेट सौदों को बढ़ावा मिले और भाजपा नेताओं तथा मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा सरकार के करीबियों को फायदा हो? मंगलवार को जारी एक बयान में सिंघार ने कहा, "क्या 'महाकाल लोक' खुद, आपकी सरकार की देखरेख में, अब भाजपा नेताओं और आपके साथियों से जुड़े प्रॉपर्टी सौदों के लिए महज एक जरिया बनकर रह गया है?" यह मामला लगभग 45,000 वर्ग फीट जमीन के एक टुकड़े से जुड़ा है। सिंघार के बयान के मुताबिक, 2 मार्च 2026 को यूटोपिया होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन 3.82 करोड़ रुपए में खरीदी थी। कांग्रेस के दावे के अनुसार, कंपनी के डायरेक्टर विधायक चिंतामणि मालवीय और उनके बिजनेस पार्टनर इकबाल सिंह हैं। शिकायतकर्ता राजेंद्र कुवाल, जो उज्जैन के रहने वाले हैं, ने मुख्य सचिव, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में औपचारिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में एक जनहित याचिका (पीआईएल) भी दायर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 1950 और 1967-68 के राजस्व रिकॉर्ड से पता चलता है कि अधिग्रहित जमीन के कुछ हिस्से आधिकारिक तौर पर सरकारी संपत्ति के तौर पर दर्ज थे। करोड़ों रुपए की जमीन को गलत तरीके से कृषि भूमि बताकर रजिस्टर कराया गया, जिसके चलते लगभग 3.40 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की चोरी की गई। सिंघार ने कहा, "पहले महाकाल लोक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब, महाकाल की ही जमीन पर कब्जे और उसके कमर्शियल सौदों को लेकर आरोप लग रहे हैं। भाजपा सरकार ने धर्म को आस्था का विषय मानने के बजाय महज एक बिजनेस का जरिया बना दिया है।" हालांकि, विधायक मालवीय ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप 'झूठे और दुर्भावनापूर्ण' हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. मल्हारराव होल्कर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होल्कर राजवंश के संस्थापक स्व. मल्हारराव होल्कर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे संपूर्ण राष्ट्र के गौरव हैं। उन्होंने मालवा की माटी को अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम से सींचा। होल्कर राजवंश लोक-कल्याण और जनसेवा के लिए जाना जाता है। हम सभी उनसे प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

रणजीत टाइम्स
प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

वर्तमान में स्थित होकर जीवन को आनंदमय बनाने की प्रेरणा दे रहा सहजयोग

आज का मनुष्य समय के तीन आयामों—भूत, वर्तमान और भविष्य—में उलझा हुआ है, किंतु विडंबना यह है कि वह सबसे कम समय वर्तमान में जी पाता है। कुछ लोग भूतकाल की स्मृतियों, सफलताओं या असफलताओं में खोए रहते हैं, जबकि कुछ भविष्य की चिंताओं और इच्छाओं में। परिणामस्वरूप वर्तमान का अमूल्य क्षण उनसे दूर होता चला जाता है।

वास्तव में वर्तमान को वही जी पाता है जो योगी बनता है, क्योंकि भोगी का जीवन केवल सांसारिक सुख-सुविधाओं, धन और विलासिता तक सीमित रह जाता है। परंतु जीवन का वास्तविक आनंद बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में निहित है। जब हम वर्तमान में जीना आरंभ करते हैं, तभी हमारा भविष्य स्वतः ही उज्ज्वल बनने लगता है। वर्तमान ही भविष्य की नींव है। भूतकाल की असफलताओं पर खेद या सफलताओं पर अहंकार, दोनों ही वर्तमान की ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं और भविष्य को भी कठिन बना देते हैं। यदि हम अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को संतुलित रखते हुए जीवन जीना सीख लें, तभी हम सच्चे अर्थों में "वर्तमान में स्थित" हो पाते हैं। यही स्थिति योग की ओर ले जाती है। लेकिन केवल इस जन्म का ही नहीं, जन्म-जन्मांतरों के संस्कारों और अनुभवों का प्रभाव भी हमारे अचेतन मन में विद्यमान रहता है। यही प्रभाव वर्तमान जीवन में तनाव, भय, असंतुलन और मानसिक अशांति का कारण बनता है। प्रश्न यह है कि इन बंधनों से मुक्ति कैसे मिले? इसका सहज और प्रभावशाली समाधान है — सहजयोग ध्यान। सहजयोग के अनुसार हमारे सूक्ष्म तंत्र में तीन प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं। ईड़ा नाड़ी — भूतकाल और भावनाओं की नाड़ी, पिंगला नाड़ी — भविष्य और कर्म की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी — वर्तमान और संतुलन की नाड़ी. जब ये तीनों नाड़ियाँ संतुलित होती हैं, तब मनुष्य सहज रूप से वर्तमान में स्थित हो जाता है। पंचतत्व इस संतुलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से धरती तत्व ईड़ा नाड़ी को संतुलित कर व्यक्ति को भूतकाल के बोझ से मुक्त करता है।सहजयोग ध्यान के माध्यम से इस दिव्य शक्ति का अनुभव तुरंत किया जा सकता है। आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होते ही व्यक्ति अपने भीतर शांति, संतुलन और आनंद का अनुभव करने लगता है। यही अनुभव जीवन को एक नई दिशा देता है। आइए, सहजयोग से जुड़कर अतीत के बंधनों से मुक्त हों और एक आनंदमय, संतुलित एवं जागृत जीवन का अंगीकार करें।

सहजयोग पूर्णतः निशुल्क है। सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 पर संपर्क करें।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न

कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधार के लिए कई अहम निर्देश जारी

खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में नवीन कलेक्टर भवन में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुए आगामी एक सप्ताह में शत-प्रतिशत एच.पी.वी. वैक्सीन लगाए जाने के निर्देश समस्त विकासखंड चिकित्साधिकारियों को दिए। वही भीषण गर्मी एवं लू तापघात की संभावना को देखते हुए सभी डिलेवरी प्वाइंट एवं स्वास्थ्य संस्थाओं के लेबर रूम व एन.आर.सी. में ए.सी.-कूलर लगाने तथा ठंडे पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय खरगोन सहित समस्त बीएमओ को दिए गए। बैठक में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में फूड बास्केट उपलब्ध न होने पर पंचायत एवं एन.टी.पी.सी. के माध्यम से फूड बास्केट की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी माह में 70 प्रतिशत एक्स-रे लक्ष्य पूर्ण करने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करने के निर्देश भी समस्त बीएमओ को दिए गए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने प्रत्येक माह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ स्वास्थ्य विभाग की नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।

"नशे से दूरी है जरूरी" अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कलेक्टर इंदौर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा "नशे से दूरी है जरूरी" अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अभियान के तहत विद्यार्थियों, ग्रामीणजनों एवं आम नागरिकों को नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके भविष्य, परिवार एवं सामाजिक जीवन पर भी गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कार्यक्रमों में सभी को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

आबकारी निरीक्षक आशीष जैन एवं त्रियंबिका शर्मा द्वारा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एवं सत्य मेव जयते इंस्टीट्यूट में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि नशा युवाओं के भविष्य एवं उनके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। कार्यक्रम में युवाओं को स्वयं नशे से दूर रहने एवं अपने मित्रों, परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया तथा अंत में सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।

आबकारी उप निरीक्षक कृतिका द्विवेदी द्वारा ग्राम दतोदा ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणजनों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर नशे से दूर रहने हेतु प्रेरित किया गया।

आबकारी उप निरीक्षक मीना माल द्वारा ग्राम मेमदी, सिमरोल स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं एवं ग्रामीणों को जागरूक करते हुए नशा मुक्ति का संदेश दिया गया।

इसी क्रम में आबकारी उप निरीक्षक सुनील मालवीय एवं बी.डी. अहिरवार द्वारा अंकुरण नशा मुक्ति केंद्र में कार्यशाला आयोजित कर नशे से होने वाले सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों पर चर्चा की गई।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र जोशी एवं आबकारी उप निरीक्षक मीरा सिंह द्वारा अर्जुनपुरा बस्ती में जनजागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया।

सभी कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को स्वयं नशे से दूर रहने एवं समाज में अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई।

झाबुआ पुलिस द्वारा ग्राम कोदली में हुई मासूम बालक की हत्या का बड़ा खुलासा

रिपोर्टर :- सलीम हुसैन

आरोपी द्वारा अपने महंगे शौक एवं ऐशो-आराम की पूर्ति के लिए मौसी के घर में घुसकर किया प्राणघातक हमला एवं लूट

मासूम बालक की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा
पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार के निर्देशन में पेटलावद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 05.05.2026 को ग्राम कोदली निवासी मृतक उत्कर्ष पिता शैलेन्द्र नायक उम्र 06 वर्ष एवं घायल रमीलाबाई पति कुशलसिंह नायक उम्र 53 वर्ष अपने घर की छत पर गंभीर घायल अवस्था में खून से लथपथ मिले।

परिजनों द्वारा दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मासूम उत्कर्ष को मृत घोषित कर दिया। मृतक बालक का अंतिम संस्कार किए जाने के दौरान थाना प्रभारी पेटलावद निरीक्षक निर्भयसिंह भूरिया को मुखबिर से बालक की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं परिजनों व समाजजनों को समझाइश देकर पोस्टमार्टम के लिए राजी किया गया। दिनांक 06.05.2026 को हुए पोस्टमार्टम में डॉक्टरों द्वारा बालक की मृत्यु मानव द्वारा कारित चोटों से होना बताया गया। इसके आधार पर थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 226/2026 धारा 103(1), 109(1) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री देवेन्द्र पाटीदार द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीओपी पेटलावद अनुरक्ति साबनानी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक निर्भयसिंह भूरिया को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। पुलिस के द्वारा सूझबूझ से पूछताछ करने पर आरोपियों ने उक्त घटना को करना स्वीकार किया। आरोपियों के नाम— 01. जितेन्द्र उर्फ जितु पिता स्व. शंकर नायक उम्र 24 वर्ष निवासी छायन थाना राणापुर, हाल सिद्धेश्वर कॉलोनी झाबुआ 02. चिराग पिता राजेश नायक उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम कोदली । सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने महंगे शौक एवं ऐशो-आराम की पूर्ति के लिए पैसों की तलाश में थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मौसी रमीलाबाई को घर में अकेला पाकर उन पर हमला किया तथा उनके पोते उत्कर्ष की फावड़े से वार कर हत्या कर दी। आरोपियों ने रमीलाबाई के कानों से सोने के टॉप्स छीन लिए एवं घर में रखी सोने की अंगूठी एवं चांदी की चेन लूटकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पूरी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई।

अभिभावकों से अपील झाबुआ पुलिस सभी अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों एवं युवाओं की गतिविधियों, मित्र मंडली एवं खर्च करने की आदतों पर नियमित निगरानी रखें। कई बार महंगे शौक, दिखावे की प्रवृत्ति एवं गलत संगति युवा पीढ़ी को अपराध की ओर धकेल देती है। बच्चों को नैतिक शिक्षा, पारिवारिक संस्कार एवं सही मार्गदर्शन देना समाज और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है। "सजग अभिभावक ही सुरक्षित भविष्य की नींव हैं।"

तुकईथड़ अतिक्रमण मामला: विभागों की आपसी खींचतान का भू-माफिया उठा रहे फायदा

तहसीलदार कब तय करेंगे जवाबदेही ?

महेन्द्र मालवीय रणजीत टाईम्स

बुरहानपुर (ब्यूरो)। शासन एक तरफ गरीबों को आवास देने के लिए जमीनें आरक्षित कर रहा है, तो दूसरी तरफ बुरहानपुर के खकनार जनपद के ग्राम तुकईथड़ में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे बेशकीमती सरकारी जमीन की बंदरबांट चल रही है।

अनाज मंडी के पास स्थित जिस गौचर भूमि को साल 2017-18 में आबादी क्षेत्र घोषित कर स्थानीय बेघरों को पट्टे दिए जाने थे, आज उस पर रसूखदार और बाहरी लोग रातों-रात टीन-शेड डालकर पक्का अवैध कब्जा जमा रहे हैं।

हैरानी की बात यह नहीं है कि अतिक्रमण हो रहा है, हैरानी की बात यह है कि इस अवैध खेल को रोकने के बजाय स्थानीय प्रशासन और पंचायत विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे ह

फुटबॉल बनी सरकार की जमीनः पटवारी ने पंचायत पर, पंचायत ने राजस्व पर टाली जिम्मेदारी

जब तुकईथड़ के ग्रामीण इस खुली लूट की शिकायत लेकर पहुंचे, तो उन्हें प्रशासनिक गैर-जिम्मेदारी का लाइव नमूना देखने को मिला।

पटवारी का रटा-रटाया जवाब हैः "जमीन आबादी क्षेत्र की है, इसलिए अतिक्रमण हटाना हमारा नहीं, ग्राम पंचायत का काम है।"

पंचायत ने तुरंत पल्ला झाड़ते हुए कहाः "हमारा काम सिर्फ विकास का है, जमीन पर कार्रवाई का अधिकार तो केवल राजस्व विभाग के पास है।" दो विभागों की इस आपसी खींचतान और 'लेटर-वॉर' को देखकर ऐसा लगता है कि सरकारी जमीन किसी की बपौती नहीं, बल्कि फुटबॉल बन चुकी है, जिसे दोनों विभाग एक-दूसरे के पाले में धकेल रहे हैं। सवाल यह है कि इस प्रशासनिक लाचारी और तालमेल की कमी का खामियाजा गाँव के गरीब क्यों भुगतें ?

क्या मूकदर्शक बने रहेंगे नायब तहसीलदार? जानिए क्या कहता है कानून

जब पटवारी और पंचायत अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हों, तो ऐसे में पूरे उप-तहसील क्षेत्र के मुखिया यानी नायब तहसीलदार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाना और अधीनस्थों पर नियंत्रण रखना सीधे तौर पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार के कर्तव्यों में शामिल है। फिर तहसीलदार अंतर्गत पटवारी द्वारा ये कहा जाना कि पंचायत कारवाई करेगी ये समझ से परे।

पंचायत और राजस्व विभाग में समन्वय स्थापित करना

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार, भले ही जमीन ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 'आबादी क्षेत्र' की हो, लेकिन उसका मालिकाना हक हमेशा शासन के पास होता है। इसलिए, ऐसी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पास व्यापक और असीमित कानूनी अधिकार हैं। फिर भी पटवारी और पंचायत एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं, ऐसे में तहसीलदार उप-खंड मजिस्ट्रेट के रूप में दोनों विभागों को संयुक्त निर्देश दे सकता है। वह ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच को निर्देशित कर सकता है कि पंचायत अतिक्रमणकारियों की सूची और दस्तावेज तैयार करे, जिसे राजस्व अमला वैधानिक रूप से प्रक्रिया करेगा। जबकि जब पटवारी यह कहता है कि "पंचायत हटाएगी" और पंचायत कहती है "राजस्व हटाएगा", तो यह पूरी तरह से भ्रामक है। ग्राम पंचायत के पास किसी को जेल भेजने, जुर्माना लगाने या बलपूर्वक पक्का अतिक्रमण ढहाने की न्यायिक शक्ति नहीं होती। वह केवल राजस्व विभाग को सहयोग कर सकती है। कार्रवाई करने की अंतिम और वास्तविक शक्ति केवल और केवल तहसीलदार/नायब तहसीलदार के कोर्ट के पास ही है।

वो आबादी घोषित भूमि हैं ओर ग्राम पंचायत ने पट्टे दिए हैं तो वो बताए कि किसको पट्टे दिए है आबादी भूमि की जांच कर पंचायत ही बताएगी ओर मैने पटवारी को को जांच के आदेश दिया है ओर पटवारी ने मुझे लिखित में जांच रिपोर्ट बना कर नहीं दी है ओर पंचायत लिख कर दे की किसको पट्टे नहीं दिए हैं तो कार्यवाही राजस्व करेगी कविता सोलंकी नायब तहसीलदार

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले भावेश सोलंकी को मिला राहवीर योजनांतर्गत प्रशस्ति पत्र

रिपोर्टर :- सलीम हुसैन

झाबुआ परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश कार्यालय, ग्वालियर द्वारा झाबुआ निवासी श्री भावेश सोलंकी पिता विनोद सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता कर उसकी जान बचाने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। प्रशस्ति पत्र कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भेंट किया। भावेश सोलंकी सरदार भगतसिंह मार्ग, झाबुआ द्वारा 19 अगस्त 2025 को हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ित को गोल्डन ऑवर के दौरान तत्काल निकटतम अस्पताल/ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर मानवता एवं संवेदनशीलता का परिचय दिया गया। उनकी तत्परता एवं सजगता से घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सका और उसकी जान बचाई जा सकी। परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा सोलंकी के इस सराहनीय एवं प्रेरणादायी कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें "राह-वीर" के रूप में सम्मानित किया गया तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर भविष्य में भी इसी प्रकार मानव सेवा के कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती कृतिका मोहटा उपस्थित रहे।

धार में 23 मई को लगेगा विशेष आधार शिविरः 21 और 22 मई को बांटे जाएंगे टोकन

धार. डाक विभाग द्वारा आमजन को बेहतर और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत प्रधान डाकघर धार के आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन सेवा केंद्र पर आगामी 23 मई 2026 (शनिवार) को एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।

पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर धार ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को आधार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी।इस एक दिवसीय शिविर में नए पंजीकरण (New Enrollment), नाम, पता व जन्म तिथि में त्रुटि सुधार (Correction), बायोमेट्रिक अपडेट (फोटो, फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा) तथा आधार के साथ नया मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी लिंक कराने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। शिविर के दौरान सुचारू व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुविधा के लिए 21 मई और 22 मई 2026 को टोकन वितरित किए जाएंगे। धार क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर अपना टोकन प्राप्त कर इस विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नागरिक शिविर में आते समय अपने साथ आवश्यक मूल दस्तावेज (Original Documents) लाना न भूलें।

झकनावदा नकबजनी का सनसनीखेज खुलासा

रायपुरिया पुलिस ने 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 5.50 लाख का शत-प्रतिशत मशरूका जप्त

मुस्लिम बस्ती झकनावदा में सूने मकान को बनाया था निशाना, उर्स मेला देखने गया था परिवार

झकनावदा की मुस्लिम बस्ती में रहने वाले फरियादी मेहमूद पिता शकूर खान एवं आसिफ पिता आजाद खान अपने परिवार के साथ उर्स मेला देखने सरदारपुर गए हुए थे।

इसी दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। बदमाशों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर 2,22,000 नगद एवं सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए, जिनकी कुल कीमत लगभग 5.50 लाख थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रायपुरिया में तत्काल अपराध क्रमांक 156/2026, धारा 305(क), 331(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र खुलासे हेतु प्रयास किए गए।

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2,22,000 नगद एवं 3.28 लाख से अधिक के सोने-चांदी के आभूषण बरामद

पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से संदिग्धों पर लगातार निगरानी रखी गई। दिनांक 19.05.2026 की रात्रि में मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपीः 1. रिजवान पिता रमजान खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी झकनावदा 2. संग्राम पिता दरियावसिंह मखोड़, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम भुरीघाटी को विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने फरियादी के घर से चोरी गया शत-प्रतिशत मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की, जिसमेंः 2,22,000 नगद 3.28 लाख से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण कुल मशरूका कीमत लगभग 5.50 लाख शामिल है।साइबर सेल टीम एवं विशेष सहयोगी होमगार्ड सैनिक गिरधारी का विशेष योगदान रहा। इस त्वरित एवं उत्कृष्ट सफलता पर पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पूरी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

धार जिला सीएम हेल्पलाइन (वित्त विभाग) में प्रदेश के टॉप 10 में: नालछा और पीथमपुर विकासखंड की संयुक्त बीएलबीसी बैठक संपन्न

धार. अग्रणी जिला बैंक (लीड बैंक) के तत्वावधान में आज विकास भवन पीथमपुर में विकासखंड नालछा और पीथमपुर की संयुक्त ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक का शुभारंभ करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक श्री बलराम बैरागी ने सभी आगंतुक अधिकारियों और बैंकर्स का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि सीएम हेल्पलाइन के वित्त विभाग (लीड बैंक) के प्रकरणों के निराकरण में धार जिला पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 10 में शामिल है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए उन्होंने सभी विभागों और बैंकर्स के बेहतर समन्वय और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न सरकारी पोर्टल्स पर प्राप्त हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदनों की समीक्षा की गई। एलडीएम श्री बैरागी ने सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि, पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, टंट्या मामा योजना, भगवान बिरसा मुंडा योजना सहित डेयरी और मछली पालन केसीसी के लंबित आवेदनों का त्वरित निराकरण कर निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करें।

झाबुआ पुलिस द्वारा कल्याणपुरा हाट बाजार में चलाया गया जागरूकता अभियान

"जागरूकता अभियान" के तहत महिला थाना प्रभारी एवं रक्षा सखी टीम द्वारा थाना कल्याणपुरा क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुरा हाट गुजरी बाजार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणजनों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में समझाइश देते हुए कहा गया कि अपने बच्चों को कम से कम 12वीं तक नियमित रूप से स्कूल अवश्य भेजें तथा कम उम्र में बालक/बालिकाओं का विवाह न करें। साथ ही जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, उन्हें पुनः स्कूल जाने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को साइबर अपराधों से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1930, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं डायल-112 के संबंध में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में समझाइश देकर नशामुक्ति हेल्पलाइन की जानकारी भी प्रदान की गई।

यातायात नियमों की जानकारी देते हुए वाहन चलाते समय सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की गई तथा विशेष रूप से बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान "मैं हूं अभिमन्यु" अभियान के बारे में भी जानकारी दी गई। युवाओं ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए समझाइश को सुना तथा आश्वस्त किया कि गली-मोहल्लों एवं गांवों में कोई भी संदिग्ध अथवा अनजान व्यक्ति घूमता दिखाई देने पर उससे पूछताछ एवं सूचना देने का कार्य करेंगे। साथ ही महिला अपराध संबंधी जानकारी देकर महिलाओं को जागरूक किया गया।

मंदिरों की दानपेटी चोरी करने वाली गैंग पुलिस की गिरफ्त में

500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालकर पुलिस पहुंची आरोपियों तक

पत्रकार :- खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। थाना छत्रीपुरा पुलिस ने मंदिरों की दानपेटी चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों और दो बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों द्वारा थाना छत्रीपुरा और रावजी बाजार क्षेत्र के मंदिरों को निशाना बनाया गया था। पुलिस के अनुसार 17 मई 2026 को मंदिर में दानपेटी चोरी की घटना सामने आने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने करीब 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने 18-19 मई की दरमियानी रात रावजी बाजार क्षेत्र के हनुमान मंदिर में चोरी करना भी स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 29 हजार रुपये का मशरूका बरामद किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव सहित पुलिस टीम और साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दिव्यांग हितग्राही को मिली श्रवण यंत्र की सौगात

जनसुनवाई में सुनी गई दिव्यांग महिला की समस्या

झाबुआ. शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में जनसुनवाई के दौरान श्रीमती सुनीता मखोड़िया द्वारा कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के समक्ष कान की मशीन (श्रवण यंत्र) उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने बताया कि सुनने में समस्या होने के कारण उन्हें दैनिक जीवन एवं संवाद स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आवेदन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. भरसट ने तत्काल उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवश्यक परीक्षण कर हितग्राही को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए।कलेक्टर के निर्देशानुसार विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हितग्राही का परीक्षण कराया गया तथा एलिम्को से विशेष समन्वय स्थापित कर श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसके पश्चात हितग्राही श्रीमती सुनीता मखोड़िया को कलेक्टर महोदय के माध्यम से श्रवण यंत्र प्रदान किया गया।

उर्वरक वितरण में पारदर्शिता की दिशा में पहल : किसानों को ई-टोकन प्रणाली की दी जा रही जानकारी

कृषि रथ के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक एवं संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति किया जा रहा जागरूक

झाबुआ. शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के मार्गदर्शन में "कृषक कल्याण वर्ष 2026" के अंतर्गत जिले के सभी छह विकासखण्डों में 16 मई 2026 से कृषि रथों का संचालन किया जा रहा है।

निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार छह कृषि रथों के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों एवं कृषि तथा सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन तीन ग्राम पंचायतों एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों का भ्रमण कर किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है।

इसी क्रम में विकासखण्ड पेटलावद में 19 मई 2026 को आयोजित विशेष जनसुनवाई के दौरान ई-विकास उर्वरक वितरण प्रणाली अंतर्गत किसानों के लिए ई-टोकन जनरेशन हेतु विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई। हेल्प डेस्क के माध्यम से किसानों को आधार नम्बर से ई-टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया तथा उनकी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का मौके पर निराकरण किया गया।

अब तक कृषि रथों के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा 59 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर लगभग 2466 किसानों से संपर्क स्थापित किया गया है। किसानों को खरीफ मौसम की फसलों की उन्नत खेती, नवीन वैज्ञानिक तकनीकों, कृषि एवं सम्बद्ध विभागों की योजनाओं तथा कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी जा रही है। कृषि रथों के माध्यम से किसानों को मृदा नमूना परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित अनुशंसाओं के अनुसार संतुलित उर्वरक उपयोग करने की सलाह भी दी जा रही है।

परियोजना संचालक आत्मा जी. एस. त्रिवेदी ने बताया कि कृषि रथों के माध्यम से किसानों को विशेष रूप से प्राकृतिक खेती, नरवाई प्रबंधन, फसल बीमा एवं शासन द्वारा लागू की गई उर्वरक वितरण की नवीन ई-टोकन प्रणाली की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब किसानों को उनके रकबे के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा।

नई प्रणाली लागू होने से किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। साथ ही पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर उर्वरक उपलब्धता संबंधी जानकारी भी प्राप्त होगी। किसानों को आधार नम्बर के माध्यम से ई-टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा रहा है।

कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत तकनीक के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के उपयोग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन वृद्धि संबंधी योजनाओं की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की समीक्षा बैठक संपन्न

उज्जैन। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) की संभागीय शाखा भरतपुरी, उज्जैन द्वारा मंगलवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन के सभाकक्ष में उज्जैन संभाग के सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता अपेक्स बैंक के नव मनोनीत अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह यादव जी ने की। बैठक में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार गुप्ता , संभागीय शाखा प्रबंधक श्री शैलेन्द्र रावत, उज्जैन जिला बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विशेष श्रीवास्तव तथा देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच एवं आगर-मालवा जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह यादव ने वैश्विक ऊर्जा संकट के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकों से किए गए अनुरोध का उल्लेख करते हुए सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से "ईंधन बचाओ - ऊर्जा बचाओ" की अपील की। साथ ही उन्होंने "वोकल फॉर लोकल" अभियान को सशक्त बनाने और "एक पेड़ मां के नाम" वृक्षारोपण अभियान के तहत जिला बैंक मुख्यालय तथा समस्त पैक्स स्तर पर लक्ष्य पूर्ण कर पौधारोपण करने का आह्वान किया, ताकि "हरित सहकार अभियान" सहकारी समितियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण विकास का प्रभावी मॉडल बन सके।

बैठक में सदस्यता महाभियान, ऋण वितरण, वसूली, अमानत संग्रहण, टर्म लोन, पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों तथा गेहूँ उपार्जन की विस्तृत समीक्षा की गई। उज्जैन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा सदस्यता अभियान में पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंश पूंजी (लगभग 50 लाख रुपये) जमा की गई है। वर्ष 2025-26 में अल्पावधि फसल ऋण की सर्वाधिक वसूली देवास जिला बैंक द्वारा की गई।

कुछ जिला बैंकों द्वारा अमानत संग्रहण (कासा) के लक्ष्य 100 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किए गए, जबकि शेष बैंकों को लक्ष्य पूर्ति हेतु और प्रयास करने के निर्देश दिए गए। टर्म लोन वितरण में उदासीनता पर चिंता व्यक्त की गई तथा सभी जिला बैंकों को विविध उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक ऋण वितरण करने के निर्देश दिए गए। वर्तमान गेहूँ उपार्जन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

ईपीओ पेंडिंग न रहने तथा शत-प्रतिशत उपार्जित अनाज का परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।बैठक में बी-पैक्स संस्थाओं की वार्षिक आमसभा में न्यूनतम 10 सदस्य किसानों को सम्मानित करने का सुझाव भी दिया गया। बैठक के समापन पर संभागीय शाखा प्रबंधक श्री शैलेन्द्र रावत द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई

उज्जैन। मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह द्वारा विभिन्न मामलों में जनसुनवाई की गई।

घट्टिया विकासखंड के गांव नजरपुर निवासी 70 वर्षीय सायर बाई ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनके परिवार में 04 बेटे है। उनमें से 03 बेटों ने प्रार्थियां और उसके सबसे छोटे बेटे को घर से बेदखल कर दिया है तथा उनके स्वामित्व की जमीन पर भी अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है।

प्रार्थियां आर्थिक रूप से कमजोर होकर निशक्त भी है। अतः उन्हें उनके स्वामित्व की जमीन पर कब्जा दिलवाया जाए। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने एसडीएम घट्टिया को भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रार्थियां को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण कर उनकी भूमि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उज्जैन निवासी दीपिका बैरागी ने कहा कि उनके घर के सामने कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस पर नगर निगम के जोनल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। तराना के ग्राम कायथा के समस्त ग्राम वासियों ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित कई वर्ष पुराने खेतों पर आवागमन के मार्ग को कुछ लोगों द्वारा बलपूर्वक बंद कर दिया गया है। जिसके कारण ग्रामवासियों को कृषि कार्य करने में बहुत समस्या आ रही है तथा उनकी फसल का भी बहुत नुकसान हो रहा है। इस पर एसडीएम तराना को मामले की जांच कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। महिदपुर रोड़ निवासी शंकरलाल ने आवेदन दिया की गांव में उनके स्वामित्व की कृषि भूमि को उन्होंने एक व्यक्ति के पास रुपयों की आवश्यकता होने के कारण गिरवी रखा था। उनके द्वारा समय पर कर्ज चुकाने के बावजूद अनावेदक द्वारा उनकी भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ा गया है। इस पर तहसीलदार महिदपुर को मामले की जांच कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांस कूमट, एडीएम श्री अत्येन्द्र सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा 160 मामलों में जनसुनवाई की गई।

कोटी गांव श्मशान घाट की भूमि कब्जा मुक्त कराने आप ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दिव्यानंद अर्गल

ग्वालियर :- ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 59 स्थित कोटी गांव श्मशान घाट की भूमि पर कथित अवैध कब्जे के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। प्रदेश उपाध्यक्ष मनीक्षा सिंह तोमर ने कहा कि श्मशान घाट क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां अंतिम संस्कार सहित सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। पार्टी ने मांग की कि भूमि की जांच कर अवैध कब्जा हटाया जाए, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो तथा भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि को सुरक्षित घोषित किया जाए। साथ ही लंबे समय से लंबित श्मशान घाट निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की मांग भी उठाई गई। जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्रवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन कार्यक्रम में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध

एमपी ट्रांसको ने ट्रांसमिशन लॉस को पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखने में हासिल की सफलता

उज्जैन. ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने बढ़ती विद्युत मांग, सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड में एकीकरण तथा लगातार विस्तारित हो रहे ट्रांसमिशन नेटवर्क जैसी चुनौतियों के बावजूद ट्रांसमिशन लॉसेस को पिछले वर्ष के स्तर 2.60 प्रतिशत पर बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश का ट्रांसमिशन लॉसेस 2.60 प्रतिशत था तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी इसे इसी स्तर पर बनाए रखना प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की दक्षता, तकनीकी क्षमता और बेहतर प्रबंधन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग के दौरान भी यह उपलब्धि हासिल होना अत्यंत गौरव का विषय है।

नियामक आयोग के लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ट्रांसमिशन लॉसेस का लक्ष्य 2.74 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जबकि एमपी ट्रांसको ने इसे 2.60 प्रतिशत पर बनाए रखकर बेहतर प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि एमपी ट्रांसको को देश की अग्रणी ट्रांसमिशन यूटिलिटीज में शामिल करती है।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने इस उपलब्धि के लिए एमपी ट्रांसको सहित प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है । उन्होंने कहा कि सभी विद्युत कंपनियों के समन्वित प्रयास, बेहतर तकनीकी प्रबंधन एवं टीम वर्क के कारण ही मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सागर के डायल 112 हीरोज

कार में फँसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर पहुँचाया अस्पताल

भोपाल. सागर जिले के थाना बंडा क्षेत्र में डायल-112 जवानों की त्वरित प्रतिक्रिया और साहसिक कार्यवाही से सड़क दुर्घटना में कार के अंदर फँसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर समय पर उपचार उपलब्ध कराया गया। हादसे के बाद तत्काल मौके पर पहुँचकर डायल-112 टीम ने मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय दिया।

19-20 मई की मध्यरात्रि थाना बंडा क्षेत्र अंतर्गतसोनी पेट्रोल पंप के आगे सागर रोडपर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें तीन व्यक्ति घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना एक राहगीर द्वारा अपने नोडल प्वाइंटबड़ा चौराहापर तैनात डायल-112 टीम को दी गई। इसके बाद सूचना राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल में दर्ज की गई।

सजगता, सहयोग और सावधानी से सिकल सेल उन्मूलन संभव : राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल द्वारा सिकल सेल-एनीमिया जांच मशीन "गजेल" लोकार्पित

भोपाल. राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन में जागरूकता और जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है।

समय पर जांच और समुचित उपचार से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। जानकारी के अभाव में यह बीमारी माता-पिता से बच्चों तक पहुंच जाती है, लेकिन सजगता, सहयोग और सावधानी से इसका उन्मूलन संभव है। राज्यपाल श्री पटेल बुधवार को बैतूल के भीमपुर में सिकल सेल स्वास्थ्य शिविर एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उईके भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को सिकल सेल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही हैं। देशभर में लगभग 7 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन इसी दिशा में मजबूत कदम है। राज्यपाल श्री पटेल ने बैतूल जिले में सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों की सराहना की। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास" के संकल्प से सिकल सेल उन्मूलन का आह्वान किया।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि कोई भी बच्चा सिकल सेल से प्रभावित नहीं हो। इसके लिए विवाह से पूर्व लड़का और लड़की के स्वास्थ्य कार्ड का मिलान अवश्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिकल सेल उन्मूलन के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में शोध एवं उपचार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने सिकल सेल और टी.बी. मरीजों को तैलीय एवं फास्ट फूड नहीं खाने, पौष्टिक आहार लेने, नियमित व्यायाम करने तथा अनुशासित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बैगा, सहरिया और भारिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, जनजातीय ग्रामों की अधोसंरचना विकास और मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से अभूतपूर्व है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का मानचित्र तैयार कर सरकार के प्रयासों को आवश्यकताओं के अनुरूप पहुँचाने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि शिक्षा ही प्रगति और सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है। बेटियों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों, विशेषकर बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि भीमपुर में सिकल सेल जांच मशीन का लोकार्पण जनजातीय एवं वंचित समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने राज्यपाल श्री पटेल के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में चल रहे सिकल सेल जागरूकता एवं उन्मूलन प्रयासों की सराहना की।

सिकल सेल एवं थैलेसीमिया जांच मशीन "गजेल" का लोकार्पण

राज्यपाल पटेल ने कार्यक्रम में सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया जांच की अत्याधुनिक मशीन "गजेल" का लोकार्पण किया। राज्यपाल श्री पटेल को बताया गया कि मशीन जनजातीय बाहुल्य भीमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया जैसी आनुवंशिक रक्त संबंधी बीमारियों की त्वरित एवं सटीक जांच में सहायक होगी।

"मिशन रानी" अभियान का किया शुभारंभ

राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में "मिशन रानी" अभियान का भी शुभारंभ किया। अभियान में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा जनजातीय कार्य विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। यह अभियान महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती माताओं में एनीमिया नियंत्रण के लिए प्रारंभ किया गया है। अभियान का उद्देश्य एनीमिया में कमी लाना, रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार करना तथा सिकल सेल एवं थैलेसीमिया जैसी बीमारियों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत हीमोग्लोबिन जांच, संपूर्ण रक्त जांच, सीरम फेरिटिन, विटामिन बी-12 एवं विशेष रक्त परीक्षण किए जाएंगे।

हितलाभ वितरण और प्रदर्शनी अवलोकन

राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया। सिकल मित्र प्रमाण पत्र, जेनेटिक कार्ड, फूड बास्केट, मां गंगा आजीविका स्वयं सहायता समूह, सी.सी.एल. राशि प्रदान की। सी.बी.एस.ई. कक्षा 12वीं में 94 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर सेजल उईके, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शिवानी उईके तथा अंतर्राष्ट्रीय कराटे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कल्याणी कोड़पे को सम्मानित किया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, वन और स्वास्थ्य विभाग के स्टालों का भी निरीक्षण किया। विभागीय गतिविधियों, योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

कल्दा वन-धन विकास केंद्र बना जनजातीय महिला उद्यमिता का प्रतीक

भोपाल. कन्दा वन धन विकास केन्द्र जनजातीय महिला उद्यमिता का प्रतीक बन गया है। दक्षिण पन्ना में स्किल इस केन्द्र ने म.प्र. में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया है।

केंद्र द्वारा इस वर्ष लगभग 21.4 लाख रुपये का रिकॉर्ड राजस्व एवं लगभग 5 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है, जो पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में राजस्व में 400 प्रतिशत से अधिक तथा लाभ में 800 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

पूर्व वर्षों में केंद्र का राजस्व एवं लाभ क्रमशः वर्ष 2021-22 में 6.5 लाख रुपये एवं 17 हजार रुपये, वर्ष 2022-23 में 4.7 लाख रुपये एवं 67 हजार रुपये, वर्ष 2023-24 में 2.6 लाख रुपये एवं 63 हजार रुपये और वर्ष 2024-25 में 5.1 लाख रुपये एवं 22 हजार रुपये रहा था। यह वृद्धि स्थानीय संग्राहकों को बेहतर मूल्य, गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करण एवं प्रभावी विपणन रणनीतियों का परिणाम मानी जा रही है।

वन-धन विकास केंद्र कल्दा के माध्यम से स्थानीय जनजातीय संग्राहकों को लघुवनोपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक प्राप्त हो रहा है।

इसमें अचार/चिरौंजी चरवा का समर्थन मूल्य 130 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है, जबकि गुणवत्ता के आधार पर संग्राहकों को वन-धन केंद्र के माध्यम से लगभग 160 रुपये से 180 रुपये प्रति किलोग्राम तक मूल्य प्राप्त हुआ। बाद में इसी उपज का प्रसंस्करण, डीसीडिंग, सफाई एवं आकर्षक पैकेजिंग कर "कल्दा चिरौंजी" ब्रांड के रूप में विपणन किया गया। इस पहल से स्थानीय संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है तथा बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई है।

मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक होगी उज्जैन में : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली (27वीं) बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद् की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक लेने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबन्धन एवं आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 26वीं बैठक बस्तर में करके देश में नक्सलवाद की समाप्ति का जन संदेश दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण से बीते सप्ताह राज्य में हुई विशेष गतिविधियों और सरकार को मिली उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की। मध्यप्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पुलिस अधिकारी सम्मानित, मुख्यमंत्री ने दी बधाईमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को नक्सल मुक्त करने में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह द्वारा पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव सहित 'नक्सल उन्मूलन अभियान' में सक्रिय योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है।

भोजशाला पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत, मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा लाने का प्रयास करेगी सरकार-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार जिले की भोजशाला परिसर को लेकर मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने करीब 750 साल पुराने और धार्मिक/ईश वंदना से जुड़े इस मसले का सकारात्मक एवं शांतिपूर्ण समाधान किया है। सरकार इस विषय से जुड़े सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करायेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार मां वाग्देवी की वास्तविक प्रतिमा विदेश से स्वदेश लाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ हर जरूरी प्रयास एवं समन्वय करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस महत्वपूर्ण फैसले के मद्देनजर मध्यप्रदेश में शांति, सौहार्द और सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रदेशवासियों को सरकार की ओर से बधाई भी दी।

प्रधानमंत्री का सम्मान - देश का सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्हें विदेश में मिल रहा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूरे देश का सम्मान है।

कौशल प्रशिक्षण से बढ़ रहा बेटियों का आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रहे कदम

इन्दौर. प्रदेश की बेटियां अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की योजनाएं उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के बेहतर अवसर दे रही हैं।

यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ रही हैं। कौशल प्रशिक्षण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

प्रदेश में 934 आईटीआई हैं। इनमें 290 शासकीय और 644 निजी आईटीआई शामिल हैं। इन संस्थानों में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2025 में शासकीय आईटीआई में 94.55 प्रतिशत प्रवेश हुआ। यह अब तक का सर्वाधिक प्रवेश प्रतिशत है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शासकीय आईटीआई में 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है।

प्रदेश की आईटीआई में वर्तमान में 71 आधुनिक ट्रेड्स में 15 हजार से अधिक महिला प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। "कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)", "स्टेनोग्राफर हिन्दी" और "इलेक्ट्रिशियन" जैसे ट्रेडों में बड़ी संख्या में बेटियाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। यह बदलते माहौल और बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब बेटियां नए क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भविष्य को मजबूत बना रही हैं।

महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण देने के लिए प्रदेश में 7 शासकीय महिला आईटीआई संचालित की जा रही हैं। वहीं 56 शासकीय आईटीआई में महिला छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। इनमें 3400 से अधिक सीटें हैं। इससे दूर-दराज क्षेत्रों की बेटियों को भी प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है।

कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का फोकस केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। विभाग महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी लगातार काम कर रहा है। विशेष महिला प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से 777 महिला प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिला है। इंदौर स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट द्वारा 509 महिलाओं को निःशुल्क वाहन संचालन प्रशिक्षण दिया गया। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव और मजबूत हुआ है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और निर्धन वर्ग की 13 हजार से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। इससे बड़ी संख्या में बेटियों को प्रशिक्षण जारी रखने में मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के अंतर्गत हजारों बेटियों को उद्योगों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग का अवसर मिला है। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों में 5660 बेटियाँ शामिल हैं। सागर की सुश्री स्नेहा रजक और रायसेन की सुश्री लिया जैसी युवतियां प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। अब वे अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं।

महिलाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। "जीवन तरंग" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 3000 बेटियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं "यूएन वीमेन" के सहयोग से बेटियों को "स्टेम और सॉफ्ट स्किल्स" का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे बेटियाँ एडवांस तकनीक और नए कार्यक्षेत्रों से जुड़ रही हैं।

परम फाउंडेशन के माध्यम से संचालित आईटीआई कौशल कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में बेटियाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। धार जिले के सरदारपुर आईटीआई में संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है। इससे बेटियों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भी 64 हजार से अधिक बेटियों को कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिला है।

प्रदेश की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। शासकीय महिला आईटीआई बैतूल की प्रशिक्षणार्थी सुश्री त्रिशा तावड़े ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद परीक्षा में सेंट्रल ज़ोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड टॉपर्स में मध्यप्रदेश के 10 प्रतिभागियों में 5 बेटियाँ शामिल रहीं।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में भोपाल की शासकीय संभागीय आईटीआई की प्रशिक्षण अधिकारी श्रीमती प्रेमलता रहांगडाले को राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इंडिया स्किल प्रतियोगिता-2024 में प्रदेश की बेटियों ने सिल्वर, ब्रॉन्ज और मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किए। यह उपलब्धियां प्रदेश की बेटियों की क्षमता और मेहनत को दर्शाती हैं।

कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रयासों से प्रदेश की बेटियां अब आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं। कौशल प्रशिक्षण उनके लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य का मजबूत आधार बन रहा है।

सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रदर्शित किए जाएं मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन नंबर

भोपाल. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन की अध्यक्षता में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए गठित Monitoring and Implementation Framework Committee की आज मंत्रालय में बैठक हुई।

अपर मुख्य सचिव श्री राजन ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता से संबंधित टेली मानस-14416, उमंग हेल्पलाइन-14425 तथा इमरजेंसी डायल-112 प्रदर्शित करने, हेल्पलाइन नंबरों का स्कूलों एवं महाविद्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार तथा विद्यार्थियों को इनके उपयोग के प्रति जागरूक करने को कहा।

श्री राजन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं राज्य स्तर पर स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री राजन ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समितियों की बैठक प्रत्येक माह नियमित रूप से आयोजित की जाए तथा उसकी जानकारी राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलों में आयोजित होने वाली समय-सीमा बैठकों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जिससे संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री राजन ने कहा कि विद्यार्थियों के मानसिक के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा-35 में जारी दिशा-निर्देशों का सभी संबंधित विभाग गंभीरता से अध्ययन करें और उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। प्रत्येक संस्थान में काउंसलर की नियुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य रेफरल प्रणाली विकसित की जाए। गार्जियन ट्यूटर योजना/मेंटरशिप प्रणाली को प्रभावी बनाने, भेदभाव, सार्वजनिक अपमान एवं अत्यधिक शैक्षणिक दबाव पर रोक लगाने, हेल्पलाइन एवं आपात मानसिक स्वास्थ्य सहायता व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा शिक्षक एवं कर्मचारियों को नियमित मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने को कहा।

शिवपुरी पुलिस ने स्मैक के अवैध विक्रय करने वाला धरदबोचा

शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट

शिवपुरी। कोतवाली पुलिस ने एक कार्रवाई में स्मैक के अवैध विक्रय में शामिल एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 15.82 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत लगभग 4,00,000 रुपये है और एक मोटर साइकिल जिसकी कीमत 50,000 रुपये है, बरामद की गई।

आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शहर में लगातार स्मैक के विक्रय और सेवन की सूचना मिलने के बाद, पुलिस ने युवाओं के भविष्य और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नशीले पदार्थों के कारोबार और सेवन पर कार्रवाई तेज की। पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी, यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले और नगर पुलिस अधीक्षक संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई रोहित दुबे ने टीम गठित की। टीम को सूचना मिली कि होटल ग्रीन व्यू के पास पुलिया पर कोई व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस फोरेस्ट चौकी के पास पहुंची, जहां एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटर साइकिल पर बैठा दिखा और पुलिस को देखकर भागने लगा। टीम ने उसे घेरकर पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम रवि सरदार (23 वर्ष) निवासी बडागांव, थाना देहात, शिवपुरी बताया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से 15.82 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। आरोपी अवैध विक्रय की नियत से इसे रखे हुए था। मौके से आरोपी की मोटर साइकिल भी जप्त की गई। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 389/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। आरोपी से स्मैक के स्रोत के संबंध में पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि शिवपुरी को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिले और अन्य राज्यों से आने वाले नशीले पदार्थों के तस्करों की जानकारी भी एकत्रित की जा रही है। प्रशस्ति पात्र पुलिसकर्मीः इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रोहित दुबे, उनि० अमित चतुर्वेदी, उनि० सुमित शर्मा, सउनि० प्रवीण त्रिवेदी, सउनि० विवेक भट्ट, प्र. आर. 374 गजेन्द्र, प्र.आर. 489 जितेन्द्र रायपुरिया, प्र.आर. 570 विनय सिंह, प्र.आर. 890 अवतार सिंह, प्र.आर. 475 नरेश दुबे, आर. 528 महेन्द्र तोमर, आर. 285 राहुल कुमार, आर. 265 देवेन्द्र रावत, आर. 681 जितेन्द्र रावत और आर. चालक शरद यादव की विशेष भूमिका रही।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक गोपाल गावंडे द्वारा पंकज प्रिंटर्स एण्ड पैकेजिंग एलयूएन-22 सेक्टर एफ, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं जी-1, कॉस्मिक रिजेन्सी 117 गोकुल नगर कनाड़िया इंदौर म.प्र. से प्रकाशित।
प्रधान संपादक-गोपाल गावंडे (पी.आर.बी.) एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार (समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)।